जुलाई

2025

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

जुलाई 2025

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जुलाई माह में प्रकाशित खबरों का विवरण

तिथि - 1 जुलाई से 23 जुलाई तक

समाचार पत्र (अखबार) में प्रकाशित कुल खबरों की संख्या	19
डिजिटल मिडिया (न्यूज पोर्टल) में प्रकाशित कुल खबरों की संख्या	33
न्यूज चैनल पर प्रकाशित कुल खबरों की संख्या	1
जुलाई माह में प्रकाशित कुल समाचारों की संख्या	52

प्रमुख समाचार समूह जहां विभागीय खबरे प्रकाशित हुई

दैनिक जागरण	3
अमर उजाला	4
हिन्दुस्तान	1
टाइम्स ऑफ इडिया	2
हिन्दुस्तान टाइम्स	1
विश्यवार्ता	2
स्वदेश	2
अन्य	36

प्रमुख टी वी चैनल समूह जहां विभागीय खबरे प्रकाशित हुई

भारत समाचार	1

Jal Jeevan Mission impacting livelihood

PIONEER NEWS SERVICE ■
Lucknow

The Uttar Pradesh government has claimed that the state has witnessed a transformative shift through the Jal Jeevan Mission, ensuring access to clean drinking water. A joint study by international voluntary organisation WaterAid India and the Geography Department of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University across three districts — Gorakhpur, Kushinagar, and Maharajganj — confirms the mission's deep impact on public health, education, livelihoods, and social cohesion.

The study, carried out over three months, involved focused group discussions, interviews, and data analysis. With support from Panchayati Raj representatives, local bodies, and officials at district and block levels, five villages in each district were surveyed to examine the changes on the ground. The study suggested that the initiative has brought about deep-rooted and measurable improvements in the lives of rural residents in Purvanchal.

According to a report by WaterAid India, about 93% of rural households in Purvanchal now have access to clean and safe drinking water through taps. Earlier, people depended on wells, handpumps, or other sources, but now most families use tap water for drinking and cooking. This has greatly reduced the need to rely on traditional water sources.

The availability of clean water has led to a noticeable drop in waterborne and infectious diseases in rural areas. The report says that people are now experiencing fewer stomach problems, skin infections, and cases of diarrhoea. As a result, medical expenses have come down, and people are now healthier and more productive.

Under the Jal Jeevan Mission, tap connections have also been provided in schools, improving hygiene. Children now get clean drinking water, which has reduced illness and helped increase school attendance. Villagers shared that students are now going to school more regularly and dropout rates have gone down.

Local people have found employment through activities like laying pipelines, building water tanks, and maintaining the systems. This has helped improve household incomes and provided job opportunities at the village level, especially for skilled youth involved in technical work.

Earlier, women had to walk long distances to fetch water. Now, with tap water available at home, they save both time and energy. Women are using this time for other productive work. Social inequality has also reduced, improving community harmony and family well-being. The study covered five villages from each district. Most villagers who took part in the survey said the Har Ghar Jal scheme has brought about a big change in their lives. Having access to clean water has made them feel healthier, safer, and more self-reliant.

UP launches tech-driven campaign to revive 75 rivers

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: The Uttar Pradesh government is working to revive 75 small and tributary rivers across the state through a coordinated, technology-driven campaign.

Acting on the direction of Chief Minister Yogi Adityanath, a strategic plan has been implemented with support from 10 departments and leading technical institutions, a state government spokesperson said.

Divisional-level monitoring committees, led by respective Divisional Commissioners, have been formed to ensure quality and timely execution.

Institutions like IIT Kanpur, IIT BHU, IIT Roorkee, and BBAU Lucknow are providing river-specific plans based on ecological and geographical studies.

Initially launched in 2018 under MGNREGA, the campaign now includes stream cleaning, rainwater harvesting, water channeling, and plantation drives.

Ten departments—including Irrigation, Forest, Fisheries, and Rural Development—are working together at the district level.

District Ganga Committees are also involved in monitoring and encouraging public participation. The initiative aims to make water conservation and river management a core part of the state's development agenda.

UP revives 50 rivers through joint efforts

Lucknow: Aimed at water conservation and sustainability, the state govt's project to revive rivers has seen 50 rivers, spanning 3,363 km, rejuvenated through the combined efforts of the govt and locals.

Driven by Namami Gange programme and sustained through the local workforce under MNREGA, the project focused on small rivers and streams in gram panchayats to benefit the population around these river bodies.

A govt spokesperson said that the govt managed to revive small rivers and streams across 1,011 gram panchayats. "These water bodies were not only cleaned but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers," the official said. The govt has identified another 86 projects for river cleaning, deepening, embankment construction, plantation, stream restoration, and watershed development, which will be taken up under MNREGA.

The govt has also initiated a greening project aimed at preventing soil erosion and strengthening embankments. As part of this, the govt carried out plantations at 894 locations along the banks of these rivers. TNN

JAGRAN Epaper
July 13, 2025

पूर्वांचल में जल जीवन मिशन से आ रहा बदलाव

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: जल जीवन मिशन से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के भूगोल विभाग द्वारा योजना का प्रभाव जानने के लिए पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में पांच-पांच गांवों का सर्वे किया गया है। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार किए गए। अध्ययन की रिपोर्ट के

वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के अध्ययन में निकला निष्कर्ष

मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के 93 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंच रहा है। स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोग जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है और चिकित्सा खर्च कम हुआ है। महिलाओं का श्रम और समय दोनों बच रहा है। समाज में भेदभाव की स्थिति में भी कमी आई है। इसके अलावा पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई।

पूर्वांचल में ग्रामीण इलाकों के 93 फीसदी घरों तक पहुंचा नल से जल

अमर उजला ब्यूरो

स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि का संयुक्त अध्ययन

लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों के 93 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी विभाग के संयुक्त अध्ययन में ये तथ्य सामने आए। टीम ने गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया।

तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित व संक्रामक रोगों में कमी आई है। अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है।

सम्पूर्ण ई पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर

75 सूखी नदियां फिर हुईं सदानीरा

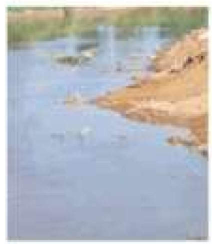

- आइआइटी समेत 10 विभागों के सदस्यों की देखरेख में चलाया जा रहा नदी कायाकल्प अभियान

राज्य ब्यूरो, जागरण • **लखनऊ :** प्रदेश की सूखी और उपेक्षित 75 नदियों में फिर से जलधारा बहने लगी है। राज्य सरकार नदियों के पुनर्जीवन को लेकर बड़ा अभियान संचालित कर रही है। इस अभियान में तकनीकी सहयोग के लिए आइआइटी जैसे संस्थानों को जोड़ा गया है, जबकि 10 प्रमुख विभागों की निगरानी में यह अभियान जमीन पर गति पकड़ रहा है। हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समितियां इस कार्य को प्रभावी बना रही हैं।

प्रदेश की नदियों को फिर से जीवित करने की पहल 2018 में मनरेगा के तहत शुरू हुई थी। अब इसे तकनीकी और संगठित रूप देकर अधिक प्रभावी बनाया गया है। सरकार का फोकस केवल जलधारा बहाल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नदी पारितंत्र को पुनर्जीवित करने पर है। इस अभियान में आइआइटी कानपुर, आइआइटी बीएचयू, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और आइआइटी रुड़की जैसे संस्थानों की मदद ली जा रही है। ये संस्थान नदियों की पारिस्थितिकी, जलधारा का इतिहास, जलग्रहण क्षेत्र और आसपास के सामाजिक व पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन कर वैज्ञानिक समाधान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने नदी पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत नदियों की सफाई, प्राकृतिक बहाव की पुनर्बहाली, जल संचयन, चैनलिंग, पौधारोपण और जनसहभागिता जैसे तत्वों को जोड़ा गया है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई, पंचायती राज, वन, उद्यान, मत्स्य, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, राजस्व व अन्य विभागों की साझेदारी भी की गई है। योजना के सतत् क्रियान्वयन के लिए हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई है।

पूर्वांचल में ग्रामीण इलाकों के 93 फीसदी घरों तक पहुंचा नल से जल

अमर उजला ब्यूरो

स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि का संयुक्त अध्ययन

लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों के 93 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी विभाग के संयुक्त अध्ययन में ये तथ्य सामने आए। टीम ने गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया।

तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित व संक्रामक रोगों में कमी आई है। अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है।

बदली पूर्वांचल की तस्वीर

सुरक्षित व विश्वसनीय पेयजल की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार

❖ वाटरएड इंडिया और गोरखपुर विवि के संयुक्त अध्ययन ने इस हकीकत पर लगाई मुहर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं।

पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है। वाटरएड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित और संक्रामक रोगों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। इससे न केवल चिकित्सा खर्च कम हुआ है, बल्कि लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ी है। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। इसका सीधा असर शैक्षिक उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे अधिक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है।

पूर्वांचल के 93% घरों तक पहुंचा नल से जल

लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों के 93 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी विभाग के संयुक्त अध्ययन में ये तथ्य सामने आए। टीम ने गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित व संक्रामक रोगों में कमी आई है। ब्यूरो

वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के संयुक्त अध्ययन ने लगाई मुहर

मोदी–योगी ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर

पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के जिलों में समूह चर्चा और साक्षात्कारों के आंकड़ों से निकला निष्कर्ष

स्वदेश समाचार ■ लखनऊ

पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

अब अधिकांश परिवार नल के पानी का कर रहे उपयोग : वाटर एड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है।

स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित और संक्रामक रोगों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। इससे न केवल चिकित्सा खर्च कम हुआ है, बल्कि लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ी है।

शिक्षा में बढ़ी भागीदारी, स्कूलों में नल कनेक्शन

जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। इसका सीधा असर शैक्षिक उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे अधिक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

स्थानीय रोजगार सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई है और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। खासकर तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को लाभ मिला है।

सामाजिक समरसता को मिला बढ़ावा

पहले जहां महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था, वहीं अब नल का जल घर तक पहुंचने से उनका श्रम और समय दोनों बच रहा है। महिलाएं अब अन्य रचनात्मक कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। समाज में भेदभाव की स्थिति में भी कमी आई है, जिससे सामाजिक समरसता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ा है।

गांवों में गहन अध्ययन, ग्रामीणों ने जताया संतोष

इस त्वरित अध्ययन में प्रत्येक जिले के पांच-पांच गांवों को शामिल किया गया। सर्वे में भाग लेने वाले अधिकतर ग्रामीणों ने माना कि हर घर जल योजना ने उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। स्वच्छ जल की उपलब्धता ने उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने का भरोसा दिया है।

आईआईटियंस के साथ मिलकर 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू

छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति कर रही निगरानी

स्वदेश समाचार ■ लखनऊ

75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से एक समन्वित रणनीति बनाई गई है। नदी पुनर्जीवन कार्य को प्रभावी और सतत बनाने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। साथ ही, जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी संस्थानों से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।

इन आईआईटी संस्थानों का लिया जा रहा सहयोग... : योगी सरकार प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रही है। इस कार्य में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उपयुक्त पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं।

संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ेगी योजना : योगी सरकार द्वारा नदियों के कायाकल्प का कार्य वर्ष 2018 से ही मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब इस कार्य को और अधिक संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत जलधाराओं की सफाई, चैनलिंग, वर्षा जल संचयन और पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

10 विभागों की देखरेख में संचालन : योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टरप्लान के अनुसार, नदी पुनर्जीवन अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए 10 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की है। इनमें सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन एजेंसी, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों के समन्वय से प्रत्येक जिले में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रदेश की 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही सरकार

लखनऊ। प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। इस काम को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से एक रणनीति बनाई गई है। निगरानी के लिए मंडल स्तर पर समिति भी बनाई गई है। सरकार नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्गदर्शन भी ले रही है। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन कर पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं। ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में 3,363 किमी नदियों का हुआ कायाकल्प

अभियान से दोबारा जीवनदायिनी बनीं 50 छोटी नदियां

स्वदेश समाचार ■ लखनऊ

योगी सरकार की जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से राज्य की सूखी और लुप्तप्राय नदियों में फिर से जीवन लौटने लगा है। अब तक 3,363 किमी में 50 नदियों का कायाकल्प हो चुका है। इससे गांवों को नई ऊर्जा और सिंचाई के लिए बेहतर साधन मिल रहे हैं।

गंगा ग्रामों में छोटे जलस्त्रोतों को दी गई नई पहचान : योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों व जलधाराओं का पुनरुद्धार कराया है। इन जलस्त्रोतों को न केवल साफ-सुथरा किया गया, बल्कि उनकी प्राकृतिक धारा को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ है और आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए।

कौशल मेला

सीईओ और

स्वदेश समाचार ■ लखनऊ

विश्व युवा कौशल दिवस के उप

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 50 नदियों का हुआ पुनरुद्धार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से कुल 50 नदियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान में बताया गया कि अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई वाली 50 नदियों का पुनरुद्धार किया गया है। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों और जल धाराओं का पुनरुद्धार कराया है। बयान में बताया गया कि मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए। जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 894 स्थलों पर सघन पौधरोपण किया गया। बयान के मुताबिक, इन पौधों को नदियों के किनारों पर लगाया गया ताकि तटबंध मजबूत हों और मिट्टी का कटाव ना हो।

बयान में बताया गया कि आने वाले वर्षों में इस पहल से हरियाली बढ़ने के साथ-साथ जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बयान के मुताबिक, प्रदेश में 3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है। बयान में बताया गया कि ये तालाब खेती, पशुपालन और पेयजल के स्रोत बनकर गांवों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने भूजल सप्ताह-2025 का किया समापन

भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है : स्वतंत्र देव सिंह

दैनिक सदमार्ग साक्षी लखनऊ। भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए।भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है। प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जज्बा और उनका संकल्प। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है।भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण / महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरूकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग हेतु आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और विभिन्न कार्यदायी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, जो कदाचित आम जन की सहभागिता से ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से स्कूल एवं कालेजों को जल संरक्षण के विभिन्न गतिविधियों में वृहद स्तर पर जोड़ा गया है। सरकारी भवनों पर न केवल अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं, अपितु फसल विविधीकरण, खेत तालाब का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, धान की सीधी बुआई तथा जल एवं मृदा संरक्षण के विविध कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० सुनील कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भूजल सप्ताह की अवधि में राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा क्लाइमेट पर चर्चा संस्था द्वारा विभिन्न स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रदर्शित चित्रकलाओं, पानी की बूँद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जनहित कल्याण सेवा समिति, बाराबंकी में आयोजित जल जागरूकता कार्यक्रम, आगा खाँ फाउण्डेशन के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट, जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा आयोजित स्कूल आउटरीच कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे जानकारी दी गई।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूजल सप्ताह-2025 का किया समापन

अनुपूरक न्यूज एजेंसी, लखनऊ

भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए।

भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है। प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरढ़ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है।

कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जढ़्बा और उनका संकल्प। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आढ़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है।

भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण / महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरूकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग हेतु आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और विभिन्न कार्यदायी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, जो कदाचित आम जन की सहभागिता से ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से स्कूल एवं कालेजों को जल संरक्षण के विभिन्न गतिविधियों में वृहद स्तर पर जोढ़ा गया है। सरकारी भवनों पर न केवल अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं, अपितु फसल विविधीकरण, खेत तालाब का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, धान की सीधी बुआई तथा जल एवं मृदा संरक्षण के विविध कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 सुनील कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भूजल सप्ताह की अवधि में राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा क्लाइमेट पर चर्चा संस्था द्वारा विभिन्न स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रदर्शित चित्रकलाओं, पानी की बूँद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जनहित कल्याण सेवा समिति, बाराबंकी में आयोजित जल जागरूकता कार्यक्रम, आगा खाँ फाउण्डेशन के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा आयोजित स्कूल आउटरीच कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे जानकारी दी गई।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूजल सप्ताह का किया समापन

चर्चित राजनीति। विशेष संवाददाता

लखनऊ। भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए। भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवं इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है। प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- **भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है**
- **जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित, भूजल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए**

आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जज्बा और उनका संकल्प। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है। भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरूकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग हेतु आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और विभिन्न कार्यदायी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, जो कदाचित आम जन की सहभागिता से ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से स्कूल एवं कालेजों को जल संरक्षण के विभिन्न गतिविधियों में वृहद स्तर पर जोड़ा गया है। सरकारी भवनों पर न केवल अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं, अपितु फसल विविधीकरण, खेत तालाब का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, धान की सीधी बुआई तथा जल एवं मृदा संरक्षण के विविध कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उप्र सुनील कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भूजल सप्ताह की अवधि में राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा क्लाइमेट पर चर्चा संस्था द्वारा विभिन्न स्कूल, कालेजों के छात्र, छात्राओं द्वारा प्रदर्शित चित्रकलाओं, पानी की बूँद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जनहित कल्याण सेवा समिति, बाराबंकी में आयोजित जल जागरूकता कार्यक्रम, आगा खॉ फाउण्डेशन के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी,

कारगिल विजय दिवस की तैयारियों का किया गया जायजा

लखनऊ, चसं। नगर निगम लखनऊ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उन वीर सपूतों की स्मृति में आयोजित किया जाता है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस बार यह आयोजन और भी विशेष होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नगर निगम पूरी तरह से सक्रिय है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने शुक्रवार को कारगिल शहीद स्मारक का दौरा कर स्थल पर चल रही तैयारियों का निरिक्षण एवं जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।

लगातार दूसरे बच्चे की इलाज के दौरान मौत

लखनऊ, चसं। राजधानी लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के चलते लगातार दूसरे दिन दूसरे बच्चे की मौत हो गई। सोमवार सुबह 3 साल के जियान की ठाकुरगंज के ऑक्सीजन हॉस्पिटल में मौत हुई थी। उसके बाद मंगलवार को मड़ियांव बंधा रोड के पुरनिया स्थित हर्ष हॉस्पिटल में 3 साल के बच्चे शशांक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर के बजाय अस्पताल संचालक और चपरासी ने इलाज किया। इसी के चलते बच्चे की मौत हुई।

CMYK

जलशक्ति मंत्री ने किया भूजल सप्ताह-2025 का समापन

जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी : स्वतंत्र देव सिंह

जलशक्ति मंत्री ने कहा,भूजल सप्ताह केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण ,जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित, भूजल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का बनाएं हिस्सा

नगर संवाददाता

लखनऊ। भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें मंगलवार को यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए।भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। जलशक्ति मंत्री ने कहा आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जज्बा और उनका संकल्प।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है।भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण व महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरूकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग के लिए आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और विभिन्न कार्यदायी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, जो कदाचित आम जन की सहभागिता से ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से स्कूल एवं कालेजों को जल संरक्षण के विभिन्न गतिविधियों में वृहद स्तर पर जोड़ा गया है। सरकारी भवनों पर न केवल अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं, अपितु फसल विविधीकरण, खेत तालाब का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, धान की सीधी बुआई तथा जल एवं मृदा संरक्षण के विविध कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उप्र सुनील कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भूजल सप्ताह की अवधि में राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा क्लाइमेट पर चर्चा संस्था द्वारा विभिन्न स्कूल व कालेजों के छात्र,छात्राओं द्वारा प्रदर्शित चित्रकलाओं, पानी की बूँद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जनहित कल्याण सेवा समिति, बाराबंकी में आयोजित जल जागरूकता कार्यक्रम, आगा खॉं फाउण्डेशन के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट, जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा आयोजित स्कूल आउटरीच कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे जानकारी दी गई।

युवा पीढ़ी भारत को जल संकट से बचा सकती है : स्वतंत्र देव सिंह

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान

- जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूजल सप्ताह-2025 का किया समापन
- जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित, भूजल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइये
- आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें

को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए। भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूंद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित

करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है। प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम्-एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जज्बा और उनका संकल्प। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है।भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण / महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरूकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग हेतु आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके।

महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार कर रही हैं कार्य : केशव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री को देश व विदेश में विपणन हेतु सरकार लगातार प्रयत्नशील है और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के शक्ति केंद्र के साबित हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार व समाज की सहभागिता से समूह स्वावलंबी

तो होंगे ही और विकास की नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। महिलाएं जो काम करती हैं, उसमें सफलता अवश्य मिलती हैं। सरकार उनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। महिला स्वयं सहायता समूह वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांति का एक केंद्र बन चुका है। आज देश एवं प्रदेश के हर जिले हर गांव में समूह की महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है।

INA NEWS

मोदी-योगी ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर- अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के संयुक्त अध्ययन ने लगाई मुहर।

Political News: पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे...

INA News_Admin

Jul 12, 2025 - 20:16

0 62

मोदी-योगी ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर

- **पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के जिलों में समूह चर्चा और साक्षात्कारों के आंकड़ों से निकला निष्कर्ष**
- **गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में परखी गई हकीकत, सुरक्षित व विश्वसनीय पेयजल की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार**
- **जल जीवन मिशन योजना से शिक्षा, आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य और रोजगार में आया बड़ा बदलाव**
- **93 फीसदी घरों तक पहुंचा नल से जल, रिपोर्ट के अनुसार जल जनित व संक्रामक रोगों में आयी गिरावट**
- **अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने के लिए कनेक्शन के पानी का करते हैं उपयोग**
- **स्कूलों में नल कनेक्शन से शिक्षा में सुधार, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी**
- **जल प्रबंधन कार्यों में स्थानीय लोगों को मिला रोजगार, महिलाओं को मिला सम्मान**

Political News: पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं।
पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

- **अब अधिकांश परिवार नल के पानी का कर रहे उपयोग**

वाटरएड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है।

- **स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण**

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित और संक्रामक रोगों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। इससे न केवल चिकित्सा खर्च कम हुआ है, बल्कि लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ी है।

- **शिक्षा में बढ़ी भागीदारी, स्कूलों में नल कनेक्शन**

जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। इसका सीधा असर शैक्षिक उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे अधिक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

- **स्थानीय रोजगार सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल**

पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई है और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। खासकर तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को लाभ मिला है।

जागरण

UP News: जल जीवन मिशन ने बदल दी पूर्वांचल की तस्वीर, 93% घरों में पहुंचा नल से जल

Jal Jeevan Mission | लखनऊ जल जीवन मिशन से पूर्वांचल के गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा और आर्थिक विकास में सुधार हुआ है। वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के अध्ययन में 93% घरों में नल से जल पहुंचने की बात सामने आई है। इससे बीमारियों में कमी आई है महिलाओं का श्रम बचा है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है।

BY **JAGRAN NEWS**
EDITED BY: **SAKSHI GUPTA**
UPDATED: SAT, 12 JUL 2025 08:57 PM (IST)

जल जीवन मिशन से पूर्वांचल में आ रहा परिवर्तन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जल जीवन मिशन से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट द्वारा योजना का प्रभाव जानने के लिए पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में पांच-पांच गांवों का सर्वे किया गया है। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार किए गए।

अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के 93 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंच रहा है। स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोग जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है और चिकित्सा खर्च कम हुआ है। महिलाओं का श्रम और समय दोनों बच रहा है।

समाज में भेदभाव की स्थिति में भी कमी आई है। इसके अलावा पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई।

The CSR Journal

Jal Jeevan Mission Transforms Rural Purvanchal: Study Reveals Major Gains in Health, Education, and Livelihoods

Header News National News

Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath, rural eastern Uttar Pradesh has witnessed a transformative shift through the Jal Jeevan Mission, ensuring access to clean drinking water.

A joint study by international voluntary organization WaterAid India and the Geography Department of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University across three districts, Gorakhpur, Kushinagar, and Maharajganj, confirms the mission's deep impact on public health, education, livelihoods, and social cohesion.

Measurable improvements

The study, carried out over three months, involved focused group discussions, interviews, and data analysis. With support from Panchayati Raj representatives, local bodies, and officials at district and block levels, five villages in each district were surveyed to examine the changes on the ground.

The study suggested that the initiative has brought about deep-rooted and measurable improvements in the lives of rural residents in Purvanchal.

Report by WaterAid India

According to a report by WaterAid India, about 93% of rural households in Purvanchal now have access to clean and safe drinking water through taps. Earlier, people depended on wells, handpumps, or other sources, but now most families use tap water for drinking and cooking. This has greatly reduced the need to rely on traditional water sources.

The availability of clean water has led to a noticeable drop in waterborne and infectious diseases in rural areas. The report says that people are now experiencing fewer stomach problems, skin infections, and cases of diarrhea. As a result, medical expenses have come down, and people are now healthier and more productive.

Jal Jeevan Mission

Under the Jal Jeevan Mission, tap connections have also been provided in schools, improving hygiene. Children now get clean drinking water, which has reduced illness and helped increase school attendance. Villagers shared that students are now going to school more regularly and dropout rates have gone down.

Local people have found employment through activities like laying pipelines, building water tanks, and maintaining the systems. This has helped improve household incomes and provided job opportunities at the village level, especially for skilled youth involved in technical work.

Social inequality reduced

Earlier, women had to walk long distances to fetch water. Now, with tap water available at home, they save both time and energy. Women are using this time for other productive work. Social inequality has also reduced, improving community harmony and family well-being.

The study covered five villages from each district. Most villagers who took part in the survey said the Har Ghar Jal scheme has brought about a big change in their lives. Having access to clean water has made them feel healthier, safer, and more self-reliant.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

नया सबेरा
www.nayasabera.com

by Naya Savera Network
Published: जुलाई 12, 2025

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के संयुक्त अध्ययन ने लगाई मुहर

पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे

पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के जिलों में समूह चर्चा और साक्षात्कारों के आंकड़ों से निकला निष्कर्ष

गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में परखी गई हकीकत, सुरक्षित व विश्वसनीय पेयजल की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार

जल जीवन मिशन योजना से शिक्षा, आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य और रोजगार में आया बड़ा बदलाव

93 फीसदी घरों तक पहुंचा नल से जल, रिपोर्ट के अनुसार जल जनित व संक्रामक रोगों में आयी गिरावट

अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने के लिए कनेक्शन के पानी का करते हैं उपयोग

स्कूलों में नल कनेक्शन से शिक्षा में सुधार, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी

जल प्रबंधन कार्यों में स्थानीय लोगों को मिला रोजगार, महिलाओं को मिला सम्मान

नया सवेरा नेटवर्क

Lucknow News: पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं।
पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

अब अधिकांश परिवार नल के पानी का कर रहे उपयोग

वाटरएड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है।

मोदी-योगी ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर, स्थानीय लोगों को मिला रोजगार, महिलाओं को सम्मान

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 12 2025 6:35PM

> तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

लखनऊ। पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

अब अधिकांश परिवार नल के पानी का कर रहे उपयोग

वाटरएड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है।

स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित और संक्रामक रोगों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। इससे न केवल चिकित्सा खर्च कम हुआ है, बल्कि लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ी है।

शिक्षा में बढ़ी भागीदारी, स्कूलों में नल कनेक्शन

जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। इसका सीधा असर शैक्षिक उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे अधिक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

स्थानीय रोजगार सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई है और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। खासकर तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को लाभ मिला है।

महिलाओं को मिला सम्मान, सामाजिक समरसता को बढ़ावा

पहले जहां महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था, वहीं अब नल का जल घर तक पहुंचने से उनका श्रम और समय दोनों बच रहा है। महिलाएं अब अन्य रचनात्मक कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। समाज में भेदभाव की स्थिति में भी कमी आई है, जिससे सामाजिक समरसता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ा है।

Posted at: Jul 12 2025 5:20PM

Prosperity is not possible without well-being of farmers: CM Yogi

Lucknow, July 12 (UNI) Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today said that India is an agrarian country and prosperity cannot be achieved without the well-being of its farmers.

Agriculture and livestock have always been closely interlinked in India. A farming household is

Tags: #Prosperity is not possible without well-being of farmers: CM Yogi

Please log in to get detailed story.

अमर उजाला

यूपी: प्रदेश की 75 छोटी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करेगी सरकार; आईटीआई संस्थानों की ली जाएगी मदद

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 13 Jul 2025 10:49 PM IST

148339 Followers लखनऊ

सार

Small rivers of Uttar Pradesh: यूपी की 75 छोटी और बड़ी नदियों की सहायक नदियों को प्रदेश सरकार जिंदा करने जा रही है। इसके लिए तकनीकी संस्थानों की मदद भी ली जाएगी।

छोटी नदियों को जिंदा करेगी सरकार। डेमो पिक। - फोटो : अमर उजाला

प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। इस काम को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से एक रणनीति बनाई गई है। निगरानी के लिए मंडल स्तर पर समिति भी बनाई गई है।

सरकार नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्गदर्शन भी ले रही है। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन कर पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं। मास्टरप्लान के अनुसार नदी पुनर्जीवन अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उप्र. राज्य जल संसाधन एजेंसी ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग सहयोग दे रहे हैं।

पर्यटन के लिहाज से 11 विरासत भवनों और किलों का होगा विकास

प्रदेश सरकार ने जर्जर हो रही राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों को नया जीवन देने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। पर्यटन विभाग प्रदेश के 11 पुराने किलों और भवनों को चमकाने की तैयारी में है। विभाग ने एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किया है। ये काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत होगा।

एजेंसियां इन जगहों का उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना विकास करेंगी। निर्धारित समय तक वह इसका संचालन करेंगी। इससे न सिर्फ इन विरासत किलों और भवनों का इतिहास बचेगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा। लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। योजना के तहत जिन 11 विरासत स्थलों का विकास किया जाएगा उसमें ललितपुर का तालभेहट किला, बांदा का रनगढ़ और भुरागढ़ किला, गोंडा की वजीरगंज बारादरी, लखनऊ का आलमबाग भवन, गुलिस्तान-ए-एरम और दर्शन विलास शामिल हैं। इसके साथ ही कानपुर की टिकैत राय बारादरी, महोबा का मस्तानी महल और सेनापति महल, झांसी का तहरौली किला और मथुरा का सीताराम महल (कोटवान किला) शामिल हैं। यह सभी जगहें अपनी खास वास्तुकला और इतिहास की कहानियों के लिए मशहूर हैं। इनका पुनरोद्धार करके इन्हें होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।

Bharat 24- UP/UK
@Bharat24Up

Translate post

CR| #BreakingNews योगी सरकार 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही
IIT के साथ मिलकर नदियों को पुनर्जीवित कर रही
अनुश्रवण समिति नदी पुनरुद्धार की निगरानी कर रही

#UttarPradesh #CMYogi #Rivers #Bharat24Digital

@CMOfficeUP @myogiadityanath @myogioffice @BJP4India

9:01 PM · Jul 13, 2025 · **98** Views

जागरण

यूपी की 75 सूखी नदियों में लौटी जीवनधारा, सरकार की बड़ी पहल से बदला परिदृश्य

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार 75 सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल में IIT संस्थानों से तकनीकी मदद ली जा रही है और 10 प्रमुख विभाग निगरानी कर रहे हैं। मनरेगा के तहत शुरू हुई इस योजना में जलधारा को बहाल करने के साथ-साथ पूरे नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

BY VIVEK RAO
EDITED BY: SAKSHI GUPTA
UPDATED: SUN, 13 JUL 2025 07:09 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की सूखी और उपेक्षित 75 नदियों में फिर से जीवनधारा बहने लगी है। राज्य सरकार नदियों के पुनर्जीवन को लेकर बड़ी पहल कर रही है। तकनीकी सहयोग के लिए आइआइटी संस्थानों को जोड़ा गया है, जबकि 10 प्रमुख विभागों की निगरानी में यह अभियान जमीन पर गति पकड़ रहा है। हर मंडल में गठित अनुश्रवण समितियां इस कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बना रही हैं।

प्रदेश की नदियों को फिर से जीवित करने की पहल की शुरुआत 2018 में मनरेगा के तहत हुई थी। अब इसे तकनीकी और संगठित रूप देकर अधिक प्रभावी बनाया गया है। सरकार का फोकस केवल जलधारा बहाल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नदी पारितंत्र को पुनर्जीवित करने पर है।

इस अभियान में आइआइटी कानपुर, आइआइटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आइआइटी रुड़की जैसे संस्थानों की मदद ली जा रही है। ये संस्थान नदियों की पारिस्थितिकी, जलधारा का इतिहास, जलग्रहण क्षेत्र और आसपास के सामाजिक व पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन कर वैज्ञानिक समाधान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने नदी पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है।

इसके तहत नदियों की सफाई, प्राकृतिक बहाव की पुनर्बहाली, जल संचयन, चैनलिंग, पौधरोपण और जनसहभागिता जैसे तत्वों को जोड़ा गया है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई, पंचायती राज, वन, उद्यान, मत्स्य, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, राजस्व व अन्य विभागों की साझेदारी भी की गई है।

योजना के सतत क्रियान्वयन के लिए हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई है। यह समिति समय-समय पर कार्यों की समीक्षा कर रही है। यह सुनिश्चित करती है कि पुनरुद्धार योजनाएं तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरी हों। जल प्रबंधन को प्राथमिकता में रखने वाली योगी सरकार ने जिला गंगा समितियों को भी इस अभियान से जोड़ा है।

ये समितियां न केवल निगरानी करती हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी जोड़कर इस कार्य को एक जन आंदोलन का रूप दे रही हैं। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि नदियों का पुनर्जीवन एक बार की परियोजना न बनकर दीर्घकालिक और टिकाऊ मॉडल बने।

अमर उजाला गांव जंक्शन

यूपी सरकार का बड़ा कदम : 75 छोटी नदियों को मिलेगा नया जीवन, आईआईटी और 10 विभाग मिलकर करेंगे कायाकल्प, जानें...

गांव जंक्शन डेस्क, लखनऊ Published by: Devesh Saraswat Updated Sun, 13 Jul 2025 05:58 PM IST

सार

उत्तर प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी के निर्देशों के तहत, इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है, जिसमें प्रदेश के 10 प्रमुख विभागों और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। - फोटो : AI

उत्तर प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी के निर्देशों के तहत, इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है, जिसमें प्रदेश के 10 प्रमुख विभागों और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को शामिल किया गया है।

आईआईटी संस्थानों से लिया जा रहा तकनीकी सहयोग

नदियों के पुनरुद्धार के इस कार्य में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रमुख संस्थानों से तकनीकी सहयोग लेने का निर्णय किया है। ये संस्थान हर नदी की विशिष्ट भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर उसके लिए उपयुक्त पुनर्जीवन योजना तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा नदियों के कायाकल्प का कार्य मनरेगा योजना के तहत साल 2018 से ही चलाया जा रहा था। लेकिन अब इसे और अधिक संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जलधाराओं की सफाई, चैनलिंग, वर्षा जल संचयन और व्यापक स्तर पर पौधरोपण जैसे कार्य किए जाएंगे।

10 विभागों की देखरेख में होगा संचालन

सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टरप्लान के अनुसार, नदी पुनर्जीवन अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए 10 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इनमें सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन एजेंसी, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए हर मंडल में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित मंडलायुक्त करेंगे। यह समिति पुनरुद्धार की योजनाओं का नियमित रूप से परीक्षण करेगी और उनकी प्रगति की समीक्षा करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि काम समय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो।

जिला गंगा समितियों की भी अहम भूमिका

इस अभियान में जिला गंगा समितियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर नदी तंत्र की निगरानी करने के साथ-साथ जन सहभागिता को बढ़ावा देंगी। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नदी पुनर्जीवन की यह प्रक्रिया एक सतत और समावेशी प्रक्रिया बन सके।

India News UP/UK
@IndiaNewsUP_UK

Translate post

आईआईटियन्स के साथ मिलकर प्रदेश की 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही योगी सरकार,
जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति कर रही निगरानी
@CMOfficeUP

किसान INDIA

यूपी की 75 सूखी नदियां होंगी जिंदा, सरकार ने शुरू किया पुनर्जीवन मिशन

बरसों से सूख चुकी नदियां, जो कभी गांवों की जीवनरेखा थीं, अब या तो नाले बन चुकी हैं या पूरी तरह गायब हो चुकी हैं. इस पहल से न सिर्फ जल संकट से निपटा जा सकेगा, बल्कि जैव विविधता, कृषि और ग्रामीण आजीविका को भी नया सहारा मिलेगा.

किसान
Kisan India
नई दिल्ली | Published: 14 Jul, 2025 | 12:00 PM

यूपी की लुप्त होती 75 धाराओं को फिर से किया जाएगा जीवंत फोटो क्रेडिट: pexels

उत्तर प्रदेश में नदियों को लेकर एक नई शुरुआत हो गई है. अब सिर्फ गंगा-यमुना ही नहीं, बल्कि प्रदेश की 75 छोटी नदियों और सहायक धाराओं को भी नया जीवन मिलने जा रहा है. **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश** पर यह योजना एक मिशन मोड में शुरू की गई है, जिसमें तकनीकी संस्थानों से लेकर 10 विभागों तक की भागीदारी है.

तकनीकी सहयोग और विभागीय तालमेल

द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, इस अभियान में IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की और BBAU लखनऊ जैसे शीर्ष तकनीकी संस्थान शामिल हैं, जो हर नदी के भूगोल, पारिस्थितिकी और सामाजिक संरचना का अध्ययन करके अलग-अलग प्लान बना रहे हैं. साथ ही, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, **बागवानी**, मत्स्य, नगर विकास, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और राजस्व विभाग, सभी मिलकर जमीन पर काम को अंजाम दे रहे हैं.

जिला और मंडल स्तर पर निगरानी

हर मंडल में आयुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई है, जो काम की गुणवत्ता और समय पर प्रगति सुनिश्चित करेगी. वहीं जिला गंगा समितियों को स्थानीय निगरानी और जनभागीदारी को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि यह अभियान सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी बने.

क्या होगा काम?

इन **नदियों की सफाई**, जल मार्गों का पुनर्निर्धारण, वर्षा जल संचयन और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा. यह सब MNREGA जैसी योजनाओं के माध्यम से 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत हो चुका है.

क्यों जरूरी है यह पहल?

बरसों से सूख चुकी नदियां, जो कभी गांवों की जीवनरेखा थीं, अब या तो नाले बन चुकी हैं या पूरी तरह गायब हो चुकी हैं. इस पहल से न सिर्फ जल संकट से निपटा जा सकेगा, बल्कि जैव विविधता, कृषि और ग्रामीण आजीविका को भी नया सहारा मिलेगा.

नया सबेरा
www.nayasabera.com

Lucknow News: आईआईटियन्स के साथ मिलकर प्रदेश की 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही योगी सरकार

by Naya Savera Network
Published: जुलाई 13, 2025

-जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति कर रही निगरानी
-जीर्णोद्धार की योजनाओं का नियमित परीक्षण, 10 विभागों के सदस्यों की देखरेख में चल रहा नदी कायाकल्प अभियान
उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 2018 से चल रहा है नदी पुनर्जीवन का कार्य
-आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की मिलकर कायाकल्प में कर रहे मदद, दे रहे टेक्निकल सपोर्ट
-योगी सरकार की प्राथमिकता में शुमार है जल संरक्षण और प्रबंधन, जिला गंगा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका

नया सवेरा नेटवर्क

लखनऊ: प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से एक समन्वित रणनीति बनाई गई है। नदी पुनर्जीवन कार्य को प्रभावी और सतत बनाने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। साथ ही, जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी संस्थानों से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।

इन आईआईटी संस्थानों का लिया जा रहा सहयोग...

योगी सरकार प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रही है। इस कार्य में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उपयुक्त पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं।

PTC NEWS उत्तर प्रदेश

आईआईटियन्स के साथ मिलकर प्रदेश की 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही योगी सरकार

आईआईटियन्स के साथ मिलकर प्रदेश की 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर रही योगी सरकार

Lucknow: प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से एक समन्वित रणनीति बनाई गई है। नदी पुनर्जीवन कार्य को प्रभावी और सतत बनाने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। साथ ही, जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी संस्थानों से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।

योगी सरकार प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रही है। इस कार्य में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उपयुक्त पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं।

संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ेगी योजना

योगी सरकार द्वारा नदियों के कायाकल्प का कार्य वर्ष 2018 से ही मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब इस कार्य को और अधिक संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत जलधाराओं की सफाई, चैनलिंग, वर्षा जल संचयन और पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

10 विभागों की देखरेख में संचालन:

योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टरप्लान के अनुसार, नदी पुनर्जीवन अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए 10 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की है। इनमें सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन एजेंसी, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों के समन्वय से प्रत्येक जिले में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी अनुश्रवण समिति:

प्रक्रिया के अंतर्गत, हर मंडल में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। जिसकी अध्यक्षता संबंधित मंडलायुक्त कर रहे हैं। यह समिति पुनरुद्धार की योजनाओं का नियमित परीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य यह है कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त हो।

जिला गंगा समितियों की भूमिका भी अहम:

योगी सरकार ने जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए जिला गंगा समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की गई है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर नदी तंत्र की निगरानी और जन सहभागिता को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करती हैं कि नदी का पुनर्जीवन एक सतत और समावेशी प्रक्रिया बन सके।

सीएम योगी के प्रयासों से यूपी में 3363 किमी नदियों का हुआ कायाकल्प

July 16, 2025 / Dainik athah

- योगी सरकार के अभियान से दोबारा जीवनदायिनी बनीं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी नदियां
- एक हजार ग्यारह 'गंगा ग्राम पंचायतों' में छोटी नदियों का किया गया पुनरुद्धार
- नमामि गंगे के अंतर्गत किया जा रहा नदियों का कायाकल्प, 894 स्थलों को चिह्नित कर हुआ पौधरोपण
- 3388 तालाब किए गए निर्मित और सुदृढ़, गांवों को मिल रही संजीवनी
- नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 86 कार्य मनरेगा के जरिए किए गए
- राज्य की सूखी व विलुप्तप्राय नदियों में फिर से लौटने लगा है जीवन

अथाह ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से राज्य की सूखी व विलुप्तप्राय नदियों में फिर से जीवन लौटने लगा है। अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई में कुल 50 नदियों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिससे गांवों को नई ऊर्जा और किसानों को सिंचाई का बेहतर साधन मिल रहा है।

गंगा ग्रामों में छोटे जलस्रोतों को दी गई नई पहचान
योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों व जलधाराओं का पुनरुद्धार कराया है। इन जलस्रोतों को न केवल साफ-सुथरा किया गया, बल्कि उनकी प्राकृतिक धारा को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ है और आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए।

डेली वर्ल्ड

उत्तर प्रदेश: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 50 नदियों का हुआ पुनरुद्धार

राजेंद्र जितेंद्र
16 Jul 2025, 04:59 PM Updated: 04:59 PM

लखनऊ, 16 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से कुल 50 नदियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान में बताया गया कि अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई वाली 50 नदियों का पुनरुद्धार किया गया है।

बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों और जल धाराओं का पुनरुद्धार कराया है।

बयान में बताया गया कि मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए।

जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 894 स्थलों पर सघन पौधरोपण किया गया।

बयान के मुताबिक, इन पौधों को नदियों के किनारों पर लगाया गया ताकि तटबंध मजबूत हों और मिट्टी का कटाव ना हो।

बयान में बताया गया कि आने वाले वर्षों में इस पहल से हरियाली बढ़ने के साथ-साथ जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

बयान के मुताबिक, प्रदेश में 3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है।

बयान में बताया गया कि ये तालाब खेती, पशुपालन और पेयजल के स्रोत बनकर गांवों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

भाषा राजेंद्र

THE FREE PRESS JOURNAL

Uttar Pradesh News: Revival Of 50 Rivers, 3,388 Ponds Under MGNREGA & Namami Gange Boosts Water Security And Biodiversity

Uttar Pradesh has made substantial headway in river rejuvenation and rural water management through coordinated efforts under MGNREGA and the Namami Gange programme. As part of this drive, 50 dried or endangered rivers, stretching 3,363 kilometers, have been revived across the state, benefiting both the environment and rural livelihoods.

UP State Bureau | **Updated:** Thursday, July 17, 2025, 05:32 AM IST

Plantation Drive Along 894 Riverbanks Aims to Curb Erosion, Boost Biodiversity in Rural UP | File Photo

Lucknow: Uttar Pradesh has made substantial headway in river rejuvenation and rural water management through coordinated efforts under MGNREGA and the Namami Gange programme.

As part of this drive, 50 dried or endangered rivers, stretching 3,363 kilometers, have been revived across the state, benefiting both the environment and rural livelihoods. The campaign has led to the restoration of small rivers and seasonal streams across 1,011 Ganga Gram Panchayats.

This includes cleaning channels, removing encroachments, and enabling natural water flow. Groundwater levels in affected areas have shown noticeable improvement, easing water scarcity and helping farmers access better irrigation.

In parallel, 86 river-related projects have been undertaken under MGNREGA. These include desilting, embankment strengthening, river deepening, watershed development, and stream restoration, all of which aimed at improving long term water retention and flood prevention.

These tree-covered buffer zones are expected to improve climate resilience and offer environmental benefits over time. Another critical aspect of the campaign involves the construction and strengthening of 3,388 ponds across rural Uttar Pradesh.

These water bodies serve multiple purposes including irrigation, livestock care, and drinking water also provide essential support to rural communities facing seasonal drought or water stress. The broader impact of these interventions extends beyond water management.

In many places, the revival of local rivers has led to renewed cultural and community activity along riverbanks, encouraging public participation in conservation. The integrated approach is also creating rural employment, supporting sustainable development, and promoting ecological balance across the state.

IBC24

उत्तर प्रदेश: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 50 नदियों का हुआ पुनरुद्धार

उत्तर प्रदेश: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 50 नदियों का हुआ पुनरुद्धार

लखनऊ, 16 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से कुल 50 नदियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान में बताया गया कि अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई वाली 50 नदियों का पुनरुद्धार किया गया है।

बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों और जल धाराओं का पुनरुद्धार कराया है।

बयान में बताया गया कि मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए।

जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 894 स्थलों पर सघन पौधरोपण किया गया।

बयान के मुताबिक, इन पौधों को नदियों के किनारों पर लगाया गया ताकि तटबंध मजबूत हों और मिट्टी का कटाव ना हो।

बयान में बताया गया कि आने वाले वर्षों में इस पहल से हरियाली बढ़ने के साथ-साथ जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

बयान के मुताबिक, प्रदेश में 3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है।

बयान में बताया गया कि ये तालाब खेती, पशुपालन और पेयजल के स्रोत बनकर गांवों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

भाषा राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

millenniumpost
NO HALF TRUTHS

UP govt revives 50 rivers spanning 3,363 km across state

BY Team MP 17 July 2025 12:53 AM

Lucknow: Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh has witnessed significant progress in water and environmental conservation. The combined efforts under the Namami Gange programme and MGNREGA have breathed new life into the state’s dried and endangered rivers. So far, 50 rivers spanning 3,363 kilometres have been rejuvenated, providing fresh energy to villages and better irrigation options for farmers.

As part of a dedicated water conservation drive, the Yogi government has revived small rivers and streams across 1,011 Ganga Gram Panchayats. These water bodies were not only cleaned, but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers.

प्रभात खबर

यूपी सरकार की जलक्रांति, 50 नदियों का किया हुई पुनरुद्धार, किसानों को मिलेंगे ये फायदा

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे और मनरेगा योजनाओं के तहत 50 नदियों और 3388 तालाबों का पुनरुद्धार किया है. जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में खेती, पेयजल और जैव विविधता को मजबूती प्रदान कर रही है.

By **Shashank Baranwal** | July 16, 2025 7:16 PM

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है. नमामि गंगे और मनरेगा योजनाओं के तहत अब तक राज्य की 50 नदियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है. सरकारी बयान के अनुसार, इन नदियों की कुल लंबाई 3363 किलोमीटर है.

गंगा ग्रामों में भी विशेष पहल

सरकार ने जल संरक्षण के प्रयासों के तहत 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों और जलधाराओं को पुनर्जीवित किया है. इन कार्यों के तहत नदियों की सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, जलधारा पुनर्स्थापन और पौधरोपण जैसे कार्य शामिल हैं.

पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण

राज्य भर में 894 स्थानों पर सघन पौधरोपण किया गया है. खासतौर पर नदियों के किनारे, जिससे तट बंधों को मजबूती मिल सके और मिट्टी का कटाव रोका जा सके. सरकार का कहना है कि इससे हरियाली और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा.

तालाब बने ग्रामीणों की जीवन रेखा

इसके अलावा, प्रदेश में 3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है. इन नदियों का पुनरुद्धार किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा. ये तालाब खेती, पशुपालन और पेय जल का अहम स्रोत बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं.

PRESS TRUST OF INDIA
India's premier news agency

UP rejuvenates 50 rivers, boosts water conservation under Namami gange and MGNREGA

LUCKNOW: (Jul 16) In a major push for water conservation, the Uttar Pradesh government has successfully rejuvenated 50 rivers spanning 3,363 kilometres through the joint efforts under the Namami Gange programme and MGNREGA.

As part of the drive, small rivers and streams have been revived across 1,011 Ganga Gram Panchayats.

According to an official statement, these water bodies were not only cleaned but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers.

The Statesman

UP govt undertakes 86 projects under MGNREGA for river restoration

Uttar Pradesh has witnessed significant progress in water and environmental conservation. The combined efforts under the Namami Gange program and MGNREGA have breathed new life into the state's dried and endangered rivers.

Statesman News Service | Lucknow | July 16, 2025 4:21 pm

Uttar Pradesh has witnessed significant progress in water and environmental conservation. The combined efforts under the Namami Gange program and MGNREGA have breathed new life into the state's dried and endangered rivers.

Officials said here on Wednesday that so far, 50 rivers spanning 3,363 kilometers have been rejuvenated, providing fresh energy to villages and better irrigation options for farmers.

As part of a dedicated water conservation drive, the UP government has revived small rivers and streams across 1,011 Ganga Gram Panchayats. These water bodies were not only cleaned but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers.

Additionally, under MGNREGA, 86 more projects have been identified for river cleaning, deepening, embankment construction, plantation, stream restoration, and watershed development.

Notably, to protect water sources and maintain environmental balance, the Yogi government has carried out intensive plantations at 894 locations, especially along riverbanks. These trees help strengthen embankments and prevent soil erosion. Over time, this initiative is expected to boost greenery and support biodiversity.

The state has also built and strengthened 3,388 ponds, increasing water storage capacity in rural areas. These ponds have become vital for farming, livestock, and drinking water, proving to be a lifeline for villages and strengthening the rural economy.

Notably, the revival of rivers has not only improved the environment, but also restored the significance of cultural and religious sites near these water bodies. People are now more aware of the importance of water conservation and are actively participating in local efforts. This initiative by the UP government has emerged as an effective strategy to address water scarcity, create rural employment, and sustain ecological balance in Uttar Pradesh.

ThePrint

UP rejuvenates 50 rivers, boosts water conservation under Namami gange and MGNREGA

PTI 16 July, 2025 07:05 pm IST

Screengram of ANI video where Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad explains reasons behind slapping canteen staff | X@ANI

Lucknow, Jul 16 (PTI) In a major push for water conservation, the Uttar Pradesh government has successfully rejuvenated 50 rivers spanning 3,363 kilometres through the joint efforts under the Namami Gange programme and MGNREGA.

As part of the drive, small rivers and streams have been revived across 1,011 Ganga Gram Panchayats.

According to an official statement, these water bodies were not only cleaned but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers.

In addition, 86 more projects have been identified under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) for river cleaning, deepening, plantation, embankment construction, stream restoration and watershed development.

The state government has also undertaken intensive plantation drives at 894 locations, especially along riverbanks. These trees help strengthen embankments and prevent soil erosion, the statement added.

The state has constructed and reinforced 3,388 ponds, significantly increasing water storage capacity in rural areas. PTI COR CDN SMV HIG

THE TIMES OF INDIA

UP revives 50 rivers through joint efforts

Lucknow: Aimed at water conservation and sustainability, the state govt's project to revive rivers has seen 50 rivers, spanning 3,363 km, rejuvenated through the combined efforts of the govt and locals.

Driven by the Namami Gange programme and sustained through the local workforce under MNREGA, the project focused on small rivers and streams in gram panchayats to benefit the population around these river bodies.

A govt spokesperson said that the govt managed to revive small rivers and streams across 1,011 gram panchayats. "These water bodies were not only cleaned but also restored to their natural flow, leading to a noticeable rise in groundwater levels and easing water scarcity for local farmers," the official said. The govt has identified another 86 projects for river cleaning, deepening, embankment construction, plantation, stream restoration, and watershed development, which will be taken up under MNREGA.

The govt has also initiated a greening project aimed at preventing soil erosion and strengthening embankments. As part of this, the govt carried out plantations at 894 locations along the banks of these rivers. It also built and strengthened 3,388 ponds, increasing water storage capacity in rural areas and helping farmers, livestock, etc.

"The revival of rivers has not only improved the environment but also restored the significance of cultural and religious sites near these water bodies. People are now more aware of the importance of water conservation and are actively participating in local efforts. This initiative by the state govt has emerged as an effective strategy to address water scarcity, create rural employment, and sustain ecological balance in UP," the official added.

उत्तरप्रदेश / राज्य

Uttar Pradesh River: सीएम योगी के प्रयासों से यूपी में 3363 किमी नदियों का हुआ कायाकल्प

16 July 2025 - by **Indiapost News Desk**

Uttar Pradesh River: – *योगी सरकार के अभियान से दोबारा जीवनदायिनी बनीं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी नदियां*

– *एक हजार ग्यारह 'गंगा ग्राम पंचायतों' में छोटी नदियों का किया गया पुनरुद्धार*

लखनऊ, 16 जुलाई: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत किए जा रहे प्रयासों से राज्य की सूखी व विलुप्तप्राय नदियों में फिर से जीवन लौटने लगा है। अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई में कुल 50 नदियों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिससे गांवों को नई ऊर्जा और किसानों को सिंचाई का बेहतर साधन मिल रहा है।

गंगा ग्रामों में छोटे जलस्रोतों को दी गई नई पहचान

योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों व जलधाराओं का पुनरुद्धार कराया है। इन जलस्रोतों को न केवल साफ-सुथरा किया गया, बल्कि उनकी प्राकृतिक धारा को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ है और आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई, गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए गए।

894 स्थलों पर पौधरोपण से मिला हरियाली को बढ़ावा

जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 894 स्थलों पर सघन पौधरोपण किया गया। इन पौधों को नदियों के किनारों पर लगाया गया जिससे तटबंध मजबूत हों और मिट्टी का कटाव न हो। यह कदम आने वाले वर्षों में हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ जैव विविधता को भी प्रोत्साहित करेगा।

3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में 3388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है। ये तालाब खेती, पशुपालन और पेयजल के स्रोत बनकर गांवों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व भी बढ़ा

नदियों के पुनरुद्धार से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं सुधरा बल्कि कई स्थानों पर इन जलधाराओं से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का महत्व भी बढ़ा है। लोग अब इन जलस्रोतों को लेकर जागरूक हुए हैं और स्थानीय स्तर पर भी संरक्षण के प्रयासों में सहभागिता निभा रहे हैं। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को जल संकट से उबारने, ग्रामीणों को रोजगार देने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की एक सशक्त व कारगर रणनीति बनकर उभरी है।।

UP govt undertakes 86 projects under MGNREGA for river restoration

Lucknow, July 16 (UNI) Uttar Pradesh has witnessed significant progress in water and environmental conservation.

The combined efforts under the Namami Gange program and MGNREGA have breathed new life into the state's dried and endangered rivers. **Please log in to get detailed story.**

Tags: #UP govt undertakes 86 projects under MGNREGA for river restoration

24 घण्टे ONLINE

भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है: स्वतंत्र देव

by Writer D — 22/07/2025 in उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ

Swatantra Dev

लखनऊ: भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev) ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह-2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए।

भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।

प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रुफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आज, जल संरक्षण मात्र एक जरुरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।

भारत समाचार | Bharat Samachar
@bstvlive

Translate post

🚨लखनऊ : भूजल सप्ताह कार्यक्रम का समापन समारोह🚨

🗣️ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का बयान
🌍 राष्ट्र का भविष्य युवाओं के पास है- स्वतंत्रदेव
💧 'प्रकृति से प्यार करने वाले समाज के हितकारी'
🌱 जल, मिट्टी और प्रकृति से प्यार करो- स्वतंत्रदेव
🚱 लोग पानी की बर्बादी बहुत करते हैं - स्वतंत्रदेव
🌊 हर जिले में एक नदी जिंदा की जा रही- स्वतंत्रदेव

#Lucknow #WaterConservation #BhoojalWeek #SwatantradevSingh @swatantrabjp

लखनऊ में भूजल सप्ताह-2025 का समापन: जलशक्ति मंत्री बोले- युवा पीढ़ी तय करेगी 2047 का जल सुरक्षित भारत

लखनऊ 2 दिन पहले

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक जनजागरण अभियान है, जो समाज को जल संरक्षण की ओर प्रेरित करता है।

उन्होंने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में भूजल सप्ताह-2025 के राज्य स्तरीय समाप

चेरिश टाइम्स

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूजल सप्ताह-2025 का किया समापन

Cherish Times · 1 day ago 0 10 3 minutes read

लखनऊ : भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरुकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें आज यहां गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह- 2025 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के अवसर पर कहीं। भूजल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेशव्यापी अभियान के माध्यम से सभी जनपदों, ब्लॉकों, संस्थानों एवं विद्यालयों में जल संचयन की दृष्टि से जागरुकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गए।

भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री द्वारा जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवम् इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवम् भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है। प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य रूप से स्थापना को अधिनियम के प्राविधानों में सम्मिलित किया गया है तथा इस विषय में निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना के लाभकारी परिणामों से प्रेरित होकर मा0 मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आज, जल संरक्षण मात्र एक जरूरत नहीं सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए भूजल सप्ताह जैसे कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को जोड़ने एवम् एक प्लेटफार्म तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम सब को मिलकर पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित-भविष्य सुनिश्चित करना होगा।
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ़ भूजल की उपलब्धता निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। कोई सरकार, कोई नीति, कोई तकनीक उतनी असरदार नहीं हो सकती, जितनी कि युवाओं की सोच, उनका जज़्बा और उनका संकल्प। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह भारत कैसा होगा- यह कोई और नहीं, आप तय करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसे आदतें अपनाएंगे वही भविष्य की नींव बनेगी। आपका एक कदम आने वाले भारत को जल संकट से बचा सकता है।

भूजल सप्ताह समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण / महानिदेशक उपाम द्वारा अपने उद्बोधन में जल को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संचयन एवं प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता के साथ सार्थक प्रयास किये जाने पर बल दिया गया और उपस्थित जनमानस में जागरुकता का संदेश देते हुये जल की प्रत्येक बूँद का संरक्षण, खेती किसानी, उद्योग एवं दैनिक उपभोग में जल के इष्टतम उपयोग हेतु आह्वान किया गया, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी भूगर्भ जल की उपलब्धता प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है और विभिन्न कार्यदायी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, जो कदाचित आम जन की सहभागिता से ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से स्कूल एवं कालेजों को जल संरक्षण के विभिन्न गतिविधियों में वृहद स्तर पर जोड़ा गया है। सरकारी भवनों पर न केवल अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं, अपितु फसल विविधीकरण, खेत तालाब का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, धान की सीधी बुआई तथा जल एवं मृदा संरक्षण के विविध कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 सुनील कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भूजल सप्ताह की अवधि में राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा क्लाइमेट पर चर्चा संस्था द्वारा विभिन्न स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रदर्शित चित्रकलाओं, पानी की बूँद, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जनहित कल्याण सेवा समिति, बाराबंकी में आयोजित जल जागरुकता कार्यक्रम, आगा खाँ फाउण्डेशन के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट, जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा आयोजित स्कूल आउटरीच कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे जानकारी दी गई।

जल संरक्षण को बनाएं जीवनशैली का हिस्सा: स्वतंत्रदेव

Lucknow News - -जलशक्ति मंत्री ने भूजल सप्ताह-2025 का किया समापन लखनऊ, विशेष

Tue, 22 Jul 2025, 09:20:PM
Newswrap | हिन्दुस्तान, लखनऊ

भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन जागरण है। हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है। इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरुकता तक सीमित मत रखिए। इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि भूजल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें मंगलवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित भूजल सप्ताह-2025 के समापन समारोह के अवसर पर कहीं।

Story continues below advertisement

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू, निदेशक, भूगर्भ जल सुनील कुमार वर्मा ने जल संरक्षण पर जोर दिया।

NEWS 85.IN
न्यूज 85 डाट इन
NEWS 85.IN
खबरें, जो खबर नहीं बनतीं

भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण : स्वतंत्रदेव सिंह

News85Web • July 22, 2025

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने मंगलवार को कहा कि भूजल सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन जागरण है, हमारी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प है।
उन्होने कहा " इस अभियान को सिर्फ एक सप्ताह की जागरूकता तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाइए। जिस दिन आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर-सब मिलकर जल बचाना शुरू करेंगे, उसी दिन एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा।"
भूजल सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति मंत्री ने जल की प्रत्येक बूँद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि जल हमारे ग्रह का जीवन रक्त है, जो जीवन को बनाए रखता है। प्रदेश की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका बहुआयामी है तथा इसकी उपलब्धता विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को त्वरित गति प्रदान करें एवं इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

NEWSTRACK
Just Journalism...

Lucknow News: लखनऊ में 'भूजल सप्ताह' कार्यक्रम के समापन का हुआ भव्य आयोजन, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह बोले- 'जल और प्रकृति से प्रेम करें युवा'

Lucknow News: गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में मंगलवार को भूजल सप्ताह 2025 का राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया गया।

Hemendra Tripathi
Published on: 22 July 2025 3:42 PM

Lucknow News: लखनऊ के गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में मंगलवार को भूजल सप्ताह 2025 का राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने लोगों को जल संरक्षण, प्रकृति और मिट्टी से प्रेम करने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से जल संकट के प्रति जिम्मेदारी लेने का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं के हाथ में है और वे 'प्रकृति से प्रेम करने वाले समाज के हितकारी बनें'। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह बोले- 'राष्ट्र का भविष्य युवाओं के पास है'

आपको बता दें कि भूजल सप्ताह जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन है। 16 से 22 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में भूजल संरक्षण के लिए विशेष सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह में विद्यालयों, पंचायतों, संस्थानों में जनजागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हुए। इस बीच छात्रों की सक्रिय भागीदारी, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं। आज मंगलवार को सप्ताह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं के पास है। ऐसे में जल, मिट्टी और प्रकृति से प्रेम करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक नदी पुनर्जीवित की जा रही है। लोग पानी की बर्बादी करते हैं, इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।

समर सलिल
www.samarsaleel.com

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 'भविष्य की डोर भविष्य के हाथ' कार्यक्रम का किया शुभारंभ, स्कूली छात्रों को दिलाई भूजल संरक्षण की शपथ

July 21, 2025

लखनऊ, 21 जुलाई 2025। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल लखनऊ में 'भविष्य की डोर भविष्य के हाथ' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल स्कूल आउटरीच कार्यक्रम के तहत जल संचयन एवं संरक्षण की भावना को समाज के हर वर्ग तक तीव्रता से पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।

भूजल सप्ताह-2025 का आयोजन: 'जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित'

प्रदेश में आम जनमानस को भूजल के महत्व के प्रति जागरूक करने तथा जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 से 22 जुलाई, 2025 के मध्य 'जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित' थीम के साथ भूजल सप्ताह-2025 का आयोजन किया जा रहा है।

जलशक्ति मंत्री श्री सिंह ने भूजल सप्ताह के छठवें दिन आयोजित इस कार्यक्रम में बताया कि जल संचयन अभियान को जन-आंदोलन बनाते हुए 'कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स' के थीम को उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के साथ व्यवहार में लाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के समय जल संचयन से संबंधित आधारभूत संरचनाओं जैसे चेकडैम, तालाब, कुएँ आदि का निर्माण एवं मरम्मत करना है, ताकि वर्षा की प्रत्येक बूँद का अधिकाधिक भाग संचित किया जा सके।